

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- गैरसैन विधान सभा पारिस (पे. मे. 10)
विशेष बाला एवं पे. निगम कटपडाग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गैरसैन
तहसील गैरसैन, जिला रायचूर

अनापत्ति प्रमाण पत्र
उत्तराखण्ड में जनपद गैरसैन के अन्तर्गत गैरसैन विधान सभा पारिस परियोजना के निर्माण हेतु (0.37 हे० आरक्षित वन भूमि, 4 हे० सिविल सोयम भूमि, 0 हे० वन पंचायत भूमि 0.18 हे०) अर्थात् कुल 0.55 हे० वन भूमि का 50 पे० निगम कटपडाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गैरसैन द्वारा दिनांक 25.12.10 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गैरसैन के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि गैरसैन विधान सभा पारिस प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

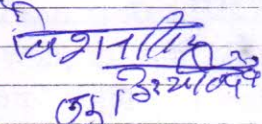
प्रयोक्ता विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि.ब. - गैरसैन (बमाली)



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 25/3/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री वि. वा. सिंह सदस्य क्षेत्र पंचायत (ता. मोरे)	 जिलाधिकारी ज. प्र. वि. वि.
2.	श्री अनिल सिंह पूर्व उपप्रधान	
3.	श्री रामाणी देवी	

ह0/—
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम : निर्मित ब्याला उपेन्द्रगढ़ जयप्रभाज
गैरसैण विधान सभा परिषद् पे.प्रो.

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैण

उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत गैरसैण विधान सभा परिषद्
पे.प्रो. ६७ (137 हे० आरक्षित वन भूमि, 18 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 18 हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ०.५५ हे० वन भूमि) का
२०११-१२ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गैरसैण) की दिनांक 14/10/15 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री के.एस.नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| 1- | श्री <u>के.एस.नेगी</u> | उपजिलाधिकारी | <u>गैरसैण जयप्रभाज</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>पी.एस.कुमार</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>पी.एस.कुमार</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>सुरेन्द्र कुमार</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>सुरेन्द्र कुमार</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री <u>आनन्द राम</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र | <u>आनन्द राम</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

गैरसैण विधान सभा परिषद् पे.प्रो. परियोजना हेतु ०.५५ हे० वन
भूमि का व्यापारिक अधिग्रहण निर्मित ब्याला उपेन्द्रगढ़

जयप्रभाज प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, गैरसैण द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसेज परिक्षेत्र के अन्तर्गत गैरसेज विकास पञ्चायत चौहरे परियोजना के निर्माण हेतु 0.55 हे० वन भूमि ~~प्रयोक्ता~~ एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- गैरसेज
जनपद- चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली मण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- गैरसेज
जनपद- चमोली

सदस्य क्षेत्र पंचायत
कार्ड सं० 14 मरोडा
वि०ख० गैरसेज (चमोली)

सदस्य क्षेत्र पंचायत
कार्ड सं० 24 रोहिड़ा
वि०ख० गैरसेज (चमोली)

शमेश्वर दिव
सदस्य क्षेत्र पंचायत
कार्ड सं० 11 सिराणा
वि०ख० गैरसेज (चमोली)

परियोजना का नाम :- गोरखगंज विधान सभा क्षेत्र के 10
निर्वाह शाखा से 10 निगम संप्रदाय

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-चम्पारण के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित ~~प्रयोजना~~ परियोजना के निर्माण हेतु 10.5.5 हे० वन भूमि संख्या 10.5.5 प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गोरखगंज तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।




जिलाधिकारी
गोरखगंज

उप जिलाधिकारी
गोरखगंज

नोट :- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण-पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

परियोजना

रसैण विधान सभा परिसर पेयजल योजना. (भराडी सैण)

निर्माण ब्राह्मण ३० पेयजल निगम कच्छ प्रभाग

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

ह0/ 
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

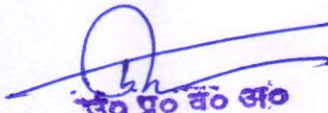
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
रुद्रगढ़

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी


राजेश्वर मिश्रा

ह0/--
जिलाधिकारी
खिलाधिकारी
चमोली


वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वनक्षेत्र गैरसैण


उ० प्र० व० अ०
गौचर (गोपेश्वर)


उप निदेशिका
गैरसैण वनक्षेत्र